# INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES




**ISSN 2277 – 9809 (online)**
**ISSN 2348 - 9359 (Print)**

*An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal*

www.IRJMSH.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

# भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन का योगदान एवं उसके राजनीतिक प्रभाव: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

**डॉ. बृजेश स्वरुप सोनकर**

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग

कर्म क्षेत्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इटावा (उ.प्र.)

## सारांश (Abstract)

वर्ष 1942 का 'भारत छोड़ो आंदोलन' (Quit India Movement) भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक युगान्तकारी घटना थी। द्वितीय विश्व युद्ध के वैश्विक क्षितिज और क्रिप्स मिशन (Cripps Mission) की विफलता की पृष्ठभूमि में आरंभ हुआ यह आंदोलन, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सबसे व्यापक और उग्र अभिव्यक्ति था। प्रस्तुत शोध पत्र राजनीति विज्ञान के परिप्रेक्ष्य से इस आंदोलन की रणनीतिक संरचना, नेतृत्वहीनता के बावजूद जन-सहभागिता, औपनिवेशिक राज्य की दमनकारी प्रतिक्रिया और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न दीर्घकालिक राजनीतिक प्रभावों का गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। यह शोध पत्र दर्शाता है कि किस प्रकार इस आंदोलन ने औपनिवेशिक सत्ता की प्रशासनिक एवं नैतिक वैधता को समाप्त कर 1947 में भारत के सत्ता हस्तांतरण के मार्ग को अपरिहार्य बना दिया।

**मुख्य शब्द (Keywords) :** भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी, औपनिवेशिक राज्य, क्रिप्स मिशन, राजनीतिक प्रभाव, समानांतर सरकारें, जन-उभार, सत्ता हस्तांतरण, राजनीति विज्ञान।

## प्रस्तावना (Introduction)

8 अगस्त 1942 को बॉम्बे (वर्तमान मुंबई) के ऐतिहासिक गोवालिया टैंक मैदान (क्रांति मैदान) में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) द्वारा पारित 'भारत छोड़ो प्रस्ताव' (Quit India Resolution) ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को सदा के लिए बदल दिया। महात्मा गांधी द्वारा दिया गया ऐतिहासिक मंत्र **"करो या मरो" (Do or Die)** केवल एक साधारण नारे का आह्वान नहीं था, अपितु ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्यसत्ता के औचित्य और उसकी संप्रभुता के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय जनमानस का अंतिम एवं अप्रत्याशित असंतोष था। इस ऐतिहासिक मोड़ ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक ऐसे निर्णयात्मक एवं अंतिम चरण में प्रविष्ट कराया जहाँ से औपनिवेशिक हुकूमत के लिए वापसी का कोई मार्ग शेष नहीं बचा था।

राजनीति विज्ञान और राज्यशास्त्र के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में, भारत छोड़ो आंदोलन पूर्वगामी अहिंसक आंदोलनों–जैसे 1920 का असहयोग आंदोलन (Non-Cooperation Movement) तथा 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन (Civil Disobedience Movement)–का मात्र क्रमिक विस्तार नहीं था। यह आंदोलन रणनीतिक, संरचनात्मक और वैचारिक तीनों स्तरों पर एक मौलिक गुणात्मक बदलाव (Qualitative Shift) का प्रतीक था। पूर्ववर्ती आंदोलनों जहाँ पूर्व-निर्धारित नियमावलियों, अनुशासित अहिंसा तथा कांग्रेस के सांगठनिक नियंत्रण में

संचालित होते थे, वहीं 1942 का आंदोलन एक स्वतःस्फूर्त जन-उभार (Spontaneous Mass Uprising) के रूप में उभरा। 9 अगस्त 1942 की भोर में ही ब्रिटिश शासन द्वारा 'ऑपरेशन ज़ीरो अवर' (Operation Zero Hour) लागू कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को रातों-रात गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया गया। इसके परिणामस्वरूप एक अभूतपूर्व नेतृत्वहीनता (Leadership Vacuum) की स्थिति उत्पन्न हुई, परंतु इसने आंदोलन को कमजोर करने के स्थान पर उसे अत्यधिक विकेंद्रीकृत और उग्र रूप प्रदान किया।

इस आंदोलन का सबसे महत्त्वपूर्ण राजनीतिक आयाम था–औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध **'जन-संप्रभुता' (Popular Sovereignty)** की व्यावहारिक स्थापना। भारत के कई क्षेत्रों, जैसे उत्तर प्रदेश के बलिया, बंगाल के तामलुक और महाराष्ट्र के सतारा में आंदोलनकारियों ने औपनिवेशिक प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह बेदखल कर समानांतर सरकारों ('प्रति सरकार' या 'जातीय सरकार') का गठन किया। इन समानांतर सरकारों ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य की 'नैतिक वैधता' (Moral Legitimacy) तथा 'प्रशासनिक संप्रभुता' (Administrative Sovereignty) पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी और भारतीय जनता स्वयं की शासन व्यवस्था संचालित करने में सक्षम थी।

द्वितीय विश्व युद्ध के वैश्विक क्षितिज, साम्राज्यवादी नीतियों के संकट, तथा क्रिप्स मिशन (Cripps Mission) की असफलता के कारण उपजे जन-असंतोष ने इस आंदोलन को एक अभूतपूर्व सामाजिक जन-आधार प्रदान किया। समाज का प्रत्येक वर्ग–छात्र, महिलाएँ, किसान, मजदूर, व्यापारी और यहाँ तक कि रियासती जनमानस–इस जन-क्रांति का अभिन्न अंग बन गया। अतः, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन का अध्ययन औपनिवेशिक राज्य के पतन, जन-आंदोलनों की गतिशीलता, शक्ति-संबंधों (Power Dynamics) में परिवर्तन तथा भारतीय राष्ट्र-राज्य के अभ्युदय की प्रक्रिया को समझने के लिए एक अनिवार्य एवं मौलिक आधार प्रस्तुत करता है।

राजनीति विज्ञान एवं आधुनिक भारतीय इतिहास के शोध-मानकों के अनुसार, शोध पत्र के लिए **'ऐतिहासिक दृष्टिकोण' (Historical Perspective / Historical Context)** का विस्तृत और गहन विश्लेषणात्मक विवरण नीचे प्रस्तुत है। इसे आप अपनी शोध समस्या (खंड 5) अथवा विषयगत विवेचन (खंड 15) के अंतर्गत एकीकृत कर सकते हैं:

## ऐतिहासिक दृष्टिकोण (Historical Perspective)

1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' के उद्भव, स्वरूप और इसके राजनीतिक परिणामों को समझने के लिए इसे केवल एक आकस्मिक घटना के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा; अपितु इसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रमिक ऐतिहासिक विकास (Historical Evolution) और तत्कालीन वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में विश्लेषित करना आवश्यक है। यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण निम्नलिखित प्रमुख संदर्भों पर आधारित है:

### 1. औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष का क्रमिक विकास (Evolution of Anti-Colonial Struggle)

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध जन-चेतना के क्रमिक परिपक्व होने की गाथा है:

- **1920-22 का असहयोग आंदोलन:** इसने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक अभिजात्य वर्गीय संगठन से उठाकर एक अखिल भारतीय 'जन-आंदोलन' (Mass Movement) में परिवर्तित किया।
- **1930-34 का सविनय अवज्ञा आंदोलन:** इसने औपनिवेशिक कानूनों को तोड़कर ब्रिटिश सत्ता की 'कानूनी वैधता' को सीधे चुनौती दी।
- **1942 का भारत छोड़ो आंदोलन:** ऐतिहासिक दृष्टि से यह असहयोग और सविनय अवज्ञा की तार्किक एवं अंतिम परिणति (Logical Culmination) था। जहाँ पूर्ववर्ती आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुधार या क्रमिक स्वशासन था, वहीं 1942 के आंदोलन का एकमात्र ऐतिहासिक लक्ष्य था–**ब्रिटिश सत्ता की तत्काल एवं पूर्ण विदाई (Immediate and Complete Withdrawal)**।

### 2. द्वितीय विश्व युद्ध एवं साम्राज्यवादी नीतियाँ (World War II & Imperialist Policies)

सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ते ही ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनमानस और प्रांतीय सरकारों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। इसके विरोध में अक्टूबर-नवंबर 1939 में 8 प्रांतों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। इस ऐतिहासिक निर्णय ने औपनिवेशिक राज्य और भारतीय राष्ट्रवाद के मध्य संवाद के अंतिम राजनीतिक सेतु को समाप्त कर दिया। इसके उपरांत 1940 का 'अगस्त प्रस्ताव' और 1941 का 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' ब्रिटिश हुकूमत को अपनी नीति बदलने पर मजबूर करने में विफल रहे।

### 3. क्रिप्स मिशन की असफलता एवं ऐतिहासिक निराशा (Failure of the Cripps Mission)

मार्च 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आए 'क्रिप्स मिशन' ने भारतीयों को युद्ध के पश्चात् केवल 'डोमिनियन स्टेटस' देने तथा भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार राज्यों को देने का प्रस्ताव रखा। इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने खारिज कर दिया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, क्रिप्स मिशन की विफलता ने भारतीय नेताओं को यह विश्वास दिला दिया कि ब्रिटिश सरकार स्वैच्छिक रूप से सत्ता का हस्तांतरण कभी नहीं करेगी। इससे राजनीतिक गतिरोध (Political Deadlock) अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया, जिसने 'भारत छोड़ो' जैसे आक्रामक कदम को ऐतिहासिक रूप से अपरिहार्य बना दिया।

### 4. दक्षिण-पूर्व एशिया में औपनिवेशिक साम्राज्य का पतन (Collapse of Imperial Powers in SE Asia)

1941-42 में जापान द्वारा सिंगापुर, मलेशिया और बर्मा (म्यांमार) पर तेजी से विजय प्राप्त की गई। इस दौरान ब्रिटिश सेना द्वारा इन क्षेत्रों को खाली करने के ऐतिहासिक तरीके ने दो प्रमुख स्थितियाँ उत्पन्न कीं:

- **ब्रिटिश अजयता (Invincibility) के भ्रम का अंत:** यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों की सैन्य पराजय ने भारतीय जनमानस में यह विश्वास पैदा किया कि साम्राज्यवादी शासन अंतहीन नहीं है।
- **नस्लीय भेदभाव का अनुभव:** बर्मा से पलायन के समय ब्रिटिश और भारतीय नागरिकों के लिए अलग-अलग रास्ते बनाए गए, जिससे भारतीयों में औपनिवेशिक सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश

जन्मा। इसके अतिरिक्त, पूर्वी भारत (विशेषकर बंगाल) में संभावित जापानी आक्रमण से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई 'विनाशकारी नीति' (Scorched Earth Policy)– जिसके तहत नावों को जब्त किया गया और खाद्यान्न की आपूर्ति बाधित हुई–ने जन-सामान्य के जीवन को संकट में डाल दिया।

**5. सामाजिक-आर्थिक असंतोष एवं जन-चेतना का ऐतिहासिक परिपाक (Socio-Economic Distress)**

युद्धकाल के दौरान अत्यधिक कर-वृद्धि, मुद्रास्फीति, और आवश्यक वस्तुओं (खाद्यान्न, मिट्टी का तेल, कपड़ा) की जमाखोरी व किल्लत ने आम जनता को भुखमरी की कगार पर ला खड़ा किया था। ऐतिहासिक अभिलेख दर्शाते हैं कि 1942 तक किसान, मजदूर, युवा और मध्यम वर्ग औपनिवेशिक राज्य के दमन से इतने आहत हो चुके थे कि वे एक अंतिम और निर्णायक संघर्ष के लिए स्वतः ही तत्पर थे।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि 1942 का आंदोलन कोई अचानक हुआ विस्फोट नहीं था, बल्कि यह औपनिवेशिक शोषण, युद्धकालीन वैश्विक संकट, और पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आंदोलनों से उपजी चेतना का ऐतिहासिक परिपाक था। इसने इतिहास के पन्नों में यह अंकित कर दिया कि अब औपनिवेशिक राज्य के पास शासन करने का न तो नैतिक अधिकार बचा था और न ही प्रशासनिक क्षमता।

## अध्ययन का महत्व एवं आवश्यकता (Significance and Need of the Study)

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1942 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में अंतिम निर्णायक प्रहार माना जाता है। राजनीति विज्ञान में शक्ति-संबंधों (Power Dynamics), औपनिवेशिक राज्य के पतन और जन-आंदोलनों के समाजशास्त्र को समझने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन का पुनर्मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक है। यह अध्ययन इस बात को रेखांकित करता है कि बिना किसी केंद्रीय संगठनात्मक ढांचे और शीर्ष नेतृत्व के अनुपस्थिति में भी किस प्रकार राष्ट्रीय चेतना औपनिवेशिक तंत्र को ध्वस्त कर सकती है।

## शोध समस्या का कथन (Statement of the Research Problem)

क्या भारत छोड़ो आंदोलन अपनी तात्कालिक विफलता एवं दमन के बावजूद, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के प्रशासनिक एवं नैतिक आधार को इस सीमा तक समाप्त करने में सफल रहा कि उसने 1947 के सत्ता हस्तांतरण को अनिवार्य बना दिया? इस शोध में आंदोलन के योगदान एवं उसके दूरगामी राजनीतिक प्रभावों का वस्तुनिष्ठ एवं राजनीतिक-वैज्ञानिक विश्लेषण समस्या का केंद्र बिंदु है।

## साहित्य की समीक्षा (Review of Literature)

- **विपिन चंद्र (1989):** अपनी पुस्तक *'भारत का स्वतंत्रता संग्राम'* में तर्क देते हैं कि 1942 का आंदोलन राष्ट्रीय चेतना की पराकाष्ठा था, जिसने स्वतंत्रता के विचार को हर भारतीय के मन में स्थायी रूप से रोपित कर दिया।

- **सुमित सरकार (1983):** *'आधुनिक भारत: 1885-1947'* में आंदोलन के स्वतःस्फूर्त स्वरूप, किसानों व मजदूरों की उग्र भागीदारी तथा समानांतर सरकारों के गठन का विस्तृत सामाजिक-राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं।
- **फ्रांसिस जी. हचिंस (1971):** *'स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन: द क्विट इंडिया मूवमेंट'* में इसे एक स्वतःस्फूर्त क्रांति के रूप में रेखांकित करते हैं, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी।
- **जवाहरलाल नेहरू (1946):** *'भारत की खोज'* में उल्लेख करते हैं कि इस आंदोलन ने भारतीय जनता में स्वाभिमान और औपनिवेशिक सत्ता के प्रति अभय की भावना उत्पन्न की।

## शोध-अंतराल (Research Gap)

पूर्ववर्ती साहित्य में अधिकांश अध्ययन भारत छोड़ो आंदोलन को केवल ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध वर्णन या स्वतंत्रता संग्राम के एक चरण के रूप में देखते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत औपनिवेशिक राज्य की 'वैधता के संकट' (Crisis of Legitimacy), जन-संप्रभुता की व्यावहारिक अभिव्यक्ति (समानांतर सरकारों के माध्यम से) तथा स्वतंत्रता उत्तर भारतीय राजनीतिक नेतृत्व के उदय के दृष्टिकोण से इस आंदोलन का एकीकृत विश्लेषण अपेक्षाकृत कम प्राप्त होता है। वर्तमान शोध पत्र इसी अंतराल की पूर्ति करता है।

## शोध के उद्देश्य (Objectives of the Research Paper)

1. 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के ऐतिहासिक एवं राजनीतिक कारणों का विश्लेषण करना।
2. आंदोलन के स्वरूप, स्वतःस्फूर्तता एवं जन-सहभागिता का अध्ययन करना।
3. औपनिवेशिक राज्य की दमनकारी नीतियों तथा आंदोलनकारियों द्वारा स्थापित समानांतर सरकारों का मूल्यांकन करना।
4. आंदोलन के दीर्घकालिक राजनीतिक प्रभावों एवं 1947 के सत्ता हस्तांतरण में इसकी भूमिका को स्पष्ट करना।

## शोध प्रश्न (Research Questions)

1. 1942 में महात्मा गांधी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 'भारत छोड़ो' का आह्वान करने के मुख्य राजनीतिक एवं आर्थिक कारक क्या थे?
2. शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का स्वरूप किस प्रकार स्वतःस्फूर्त एवं विकेंद्रीकृत हुआ?
3. समानांतर सरकारों का गठन औपनिवेशिक राज्यसत्ता के विरुद्ध किस प्रकार की राजनीतिक चुनौती था?
4. भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के प्रशासनिक एवं सैन्य ढाँचे को किस प्रकार प्रभावित किया?

## परिकल्पना (Hypothesis)

- भारत छोड़ो आंदोलन भले ही अपने तात्कालिक उद्देश्य (तत्काल स्वतंत्रता) में अल्पकालिक रूप से दबा दिया गया हो, परंतु इसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की प्रशासनिक वैधता और सैन्य वफादारी को इस सीमा तक समाप्त कर दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति केवल समय का प्रश्न बनकर रह गई।

## सैद्धांतिक आधार (Theoretical Framework)

प्रस्तुत शोध पत्र विशुद्ध रूप से राजनीति विज्ञान के राजकीय सत्ता, शक्ति-संबंधों (Power Dynamics), और संस्थागत राजनीति के स्थापित सिद्धांतों पर आधारित है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बहुआयामी राजनीतिक स्वरूप, जन-उभार, औपनिवेशिक दमन और संप्रभुता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को विश्लेषित करने के लिए निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग किया गया है:

### 1. ग्राम्शी का हेगेमनी (प्राधान्य) एवं 'सहमति के संकट' का सिद्धांत (Gramsci's Theory of Hegemony & Crisis of Consent)

इतालवी राजनीतिक चिंतक एंटोनियो ग्राम्शी (Antonio Gramsci) के **'हेगेमनी' (वैचारिक एवं नैतिक प्राधान्य)** के राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार, कोई भी शासक वर्ग अथवा औपनिवेशिक राज्य केवल दमनकारी संस्थाओं–जैसे पुलिस, सेना और दंड विधान–के भौतिक बल (Coercion) के आधार पर दीर्घकाल तक संप्रभुता बनाए नहीं रख सकता। राज्य के स्थायित्व के लिए शासित नागरिकों की **'सहमति' (Consent)** तथा शासक वर्ग का नैतिक व वैचारिक प्राधान्य अनिवार्य होता है। जब जनता यह सहमति वापस ले लेती है, तब राज्य **'वैधता के संकट' (Crisis of Legitimacy)** से ग्रस्त हो जाता है।

- **शोध में अनुप्रयोग:** राजनीति विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य के इसी 'वैचारिक एवं नैतिक प्राधान्य' के पूर्ण विनाश का प्रतीक है। महात्मा गांधी द्वारा दिए गए "करो या मरो" के संप्रभु आह्वान ने औपनिवेशिक राज्य की वैधता को चुनौती दी। जनता द्वारा औपनिवेशिक सत्ता के प्रतीकों (थाने, कचहरी, रेलवे स्टेशन) पर किया गया आक्रमण इस बात का प्रमाण था कि भारतीय जनमानस से औपनिवेशिक शासन की 'सहमति' पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी और वह केवल 'नग्न दमनकारी बल' (Naked Coercive Force) पर टिक गया था, जो कि किसी भी राजनीतिक सत्ता के पतन की प्रथम पूर्व-शर्त है।

### 2. औपनिवेशिक राज्य एवं जन-संप्रभुता का सिद्धांत (Theory of Colonial State and Popular Sovereignty)

राजनीतिक सिद्धांत एवं राज्य के स्वरूप (Nature of State) के अध्ययन यह दर्शाते हैं कि औपनिवेशिक राज्य और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के मध्य का मुख्य संघर्ष मूल रूप से **'संप्रभुता के एकाधिकार' (Monopoly of Sovereignty)** को लेकर होता है। औपनिवेशिक राज्य अपनी आरोपित सत्ता के माध्यम से राजनीतिक नियंत्रण का दावा करता है, जबकि राष्ट्रवादी आंदोलन **'जन-संप्रभुता' (Popular Sovereignty)** की पुनर्स्थापना का प्रयास करता है।

- **शोध में अनुप्रयोग:** भारत छोड़ो आंदोलन ने इस राजनीतिक सिद्धांत को एक व्यावहारिक रूप प्रदान किया। बलिया, तामलुक (मिदनापुर) और सतारा में **'समानांतर सरकारों' (Prati Sarkar)** का गठन राजनीति विज्ञान में जन-संप्रभुता के व्यावहारिक प्रकटीकरण का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जब औपनिवेशिक राज्य का प्रशासनिक ढांचा ढह गया, तब राजनीतिक समाज ने अपनी स्वायत्त संस्थाओं का निर्माण कर स्वयं अपनी संप्रभु सत्ता की स्थापना की। यह आंदोलन यह सिद्ध करता है कि राष्ट्रवाद केवल एक वैचारिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह औपनिवेशिक राज्यसत्ता के विकल्प के रूप में वैकल्पिक राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण करने की पूर्ण क्षमता रखता है।

### 3. जन-आंदोलन एवं राज्य दमन का मॉडल (Mass Movement and State Repression Model)

राजनीति विज्ञान के राजनीतिक व्यवस्था (Political Systems) और संघर्ष समाधान सिद्धांतों के अंतर्गत, जब राज्य और जनता के बीच संवाद के सभी मार्ग (जैसे क्रिप्स मिशन की विफलता) बंद हो जाते हैं, तो राजनीतिक गतिरोध (Political Deadlock) का समाधान हिंसक या तीव्र जन-संघर्ष के माध्यम से होता है।

- **शोध में अनुप्रयोग:** ब्रिटिश हुकूमत द्वारा 'ऑपरेशन ज़ीरो अवर' के तहत शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारी और उसके बाद किया गया भारी सैन्य दमन इस मॉडल की पुष्टि करता है। सैद्धांतिक रूप से, जब एक दमनकारी औपनिवेशिक राज्य जन-आकांक्षाओं को दबाने के लिए अत्यधिक बल का प्रयोग करता है, तो वह प्रतिक्रियास्वरूप 'स्वतःस्फूर्तता' (Spontaneity) को जन्म देता है, जहाँ जनता स्वयं अपनी राजनीतिक धुरी बन जाती है। इस आंदोलन ने यह रेखांकित किया कि राज्य का दमन जितना तीव्र होता है, राष्ट्रीय चेतना का प्रतिरोध उतना ही अधिक व्यापक और संगठित हो जाता है।

## शोध-पद्धति एवं शोध-प्रविधियाँ (Research Methodology)

प्रस्तुत अध्ययन में **ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक (Historical-Analytical)** तथा **गुणात्मक (Qualitative)** शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक स्रोतों (प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथों, शोध निबंधों, सरकारी अभिलेखीय संदर्भों एवं राजनीतिक विश्लेषणों) का समालोचनात्मक अध्ययन कर निष्कर्ष निष्पादित किए गए हैं।

## अध्ययन का क्षेत्र एवं सीमाएँ (Scope and Limitations)

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य अध्ययन-क्षेत्र अखिल भारतीय स्तर पर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का राजनीतिक एवं संस्थागत विश्लेषण करने तक विस्तृत है, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे उन प्रमुख क्षेत्रों के राजनीतिक परिदृश्य, जन-उभार तथा समानांतर सरकारों के गठन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, जहाँ आंदोलन अपने चरम रूप में व्यक्त हुआ था। शोध की विषयगत एवं कालानुक्रमिक सीमाओं के संदर्भ में, यह अध्ययन विशुद्ध रूप से राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक एवं संस्थागत दायरे–जैसे औपनिवेशिक राज्य की वैधता का ह्रास, संप्रभुता का हस्तांतरण, शक्ति-संबंधों में परिवर्तन और जन-आंदोलन की गतिशीलता–तक ही सीमित है। इसके अतिरिक्त, शोध पत्र की विश्वसनीयता और तथ्यात्मक शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए इसमें केवल अक्टूबर 2014 तक उपलब्ध एवं प्रामाणिक ऐतिहासिक तथ्यों, अभिलेखीय आंकड़ों तथा शोध-साहित्य का ही उपयोग किया गया है; इसके पश्चात के किसी भी कालखंडीय संदर्भ को इस अध्ययन की विषय-वस्तु से पूर्णतः पृथक रखा गया है।

## तथ्यों एवं आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण (Presentation of Facts and Data)

| क्रमांक | विषय/आयाम | तथ्य एवं आँकड़े (अक्टूबर 2014 तक के अभिलेखों के अनुसार) |
|---|---|---|
| 1. | **प्रारंभ तिथि एवं स्थान** | 8 अगस्त 1942, गोवालिया टैंक मैदान, बॉम्बे |
| 2. | **मुख्य नारा** | "करो या मरो" (Do or Die) - महात्मा गांधी |

| | | |
|---|---|---|
| **3.** | **सरकारी कार्रवाई** | 9 अगस्त 1942 की भोर में 'ऑपरेशन ज़ीरो अवर' के तहत सभी शीर्ष नेता गिरफ्तार |
| **4.** | **गिरफ्तारियाँ** | देश भर में लगभग 1,00,000 से अधिक आंदोलनकारी जेलों में बंद किए गए |
| **5.** | **शहीद/मृत्यु** | पुलिस एवं सेना की गोलाबारी में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1,028 लोग मारे गए (वास्तविक संख्या कहीं अधिक थी) |
| **6.** | **समानांतर सरकारें** | 1. बलिया (UP - चित्तू पांडे), 2. तामलुक (बंगाल - जातीय सरकार), 3. सतारा (महाराष्ट्र - प्रति सरकार) |

1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' के अभूतपूर्व स्वरूप, जन-सहभागिता तथा औपनिवेशिक राज्य की दमनकारी नीति का एक स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ खाका प्रस्तुत करते हैं। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए **"करो या मरो"** के नारे ने औपनिवेशिक शासन के प्रति भारतीय जनमानस के अंतिम असंतोष को अभिव्यक्त किया। 9 अगस्त की भोर में ही ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए गए **'ऑपरेशन ज़ीरो अवर'** के तहत शीर्ष नेतृत्व की अचानक गिरफ्तारी के बावजूद, आंदोलन का स्वतःस्फूर्त रूप से फैलना यह सिद्ध करता है कि राष्ट्रीय चेतना अब किसी संगठन विशेष तक सीमित न रहकर जन-सामान्य का संप्रभु संकल्प बन चुकी थी।

## विषयगत विवेचन एवं गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन

## (Detailed Subjective & Analytical Discussion)

### 1. पृष्ठभूमि एवं उत्प्रेरक कारक (Background and Catalytic Factors)

1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का उद्भव किसी तात्कालिक भावना का परिणाम नहीं था, अपितु यह कई वर्षों से संचित हो रहे राजनीतिक और आर्थिक असंतोष का एक विस्फोटक परिणाम था। मार्च 1942 में ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल द्वारा भेजे गए **'क्रिप्स मिशन' (Cripps Mission)** की विफलता ने भारतीय राजनीतिक वर्ग के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया कि औपनिवेशिक हुकूमत युद्ध के संकट के बावजूद भारत को वास्तविक सत्ता या पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में भारत को युद्धोपरांत केवल 'डोमिनियन स्टेटस' देने तथा प्रांतीय स्वायत्तता के नाम पर देश के संभावित विभाजन का मार्ग प्रशस्त करने की बात थी। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव की ऐतिहासिक आलोचना करते हुए इसे **"एक डूबते हुए बैंक का उत्तर-दिनांकित चेक" (A post-dated cheque on a crashing bank)** करार दिया।

राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से, द्वितीय विश्व युद्ध की वैश्विक परिस्थितियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गंभीर संकट में डाल दिया था। युद्ध के लिए जबरन धन और संसाधनों की वसूली, बेहिसाब मुद्रास्फीति (Inflation), आवश्यक वस्तुओं की भारी किल्लत और खाद्यान्न के अभाव ने आम जनता के जीवन को दयनीय बना दिया था। इसके अतिरिक्त, दक्षिण-पूर्व एशिया (विशेषकर मलेशिया, सिंगापुर और बर्मा) में ब्रिटिश सेनाओं के तेजी से पीछे हटने और वहाँ यूरोपीय नागरिकों व एशियाई नागरिकों के प्रति अपनाए गए भेदभावपूर्ण व अपमानजनक रवैये ने भारतीय जनमानस में यह अकाट्य

विश्वास पैदा कर दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य न केवल दमनकारी है, बल्कि वह भारत की रक्षा करने में भी पूरी तरह असमर्थ है। इन सभी कारकों ने मिलकर एक ऐसे विस्फोटक राजनीतिक वातावरण का निर्माण किया जहाँ एक निर्णायक जन-संघर्ष अनिवार्य हो गया था।

### 2. नेतृत्वहीनता एवं स्वतःस्फूर्त क्रांति (Leadership Vacuum and Spontaneous Revolution)

9 अगस्त 1942 की भोर में ब्रिटिश सरकार द्वारा 'ऑपरेशन ज़ीरो अवर' (Operation Zero Hour) के तहत महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना आजाद और डॉ. राजेंद्र प्रसाद सहित कांग्रेस के लगभग सभी चोटी के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय नेताओं को रातों-रात गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर नजरबंद कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत का उद्देश्य इस पूर्व-नियोजित कार्रवाई से आंदोलन को जन्म लेने से पहले ही कुचल देना था। परंतु राजनीति विज्ञान के इतिहास में यह घटना एक अनूठे विरोधाभास के रूप में दर्ज हुई; शीर्ष नेतृत्व की पूर्ण अनुपस्थिति ने आंदोलन को समाप्त करने के स्थान पर उसे और अधिक आक्रामक, विकेंद्रीकृत और **स्वतःस्फूर्त (Spontaneous)** बना दिया। इस आंदोलन ने मुख्य रूप से दो प्रमुख धाराओं या रूपों में अपनी अभिव्यक्ति दी:

1. **शहरी एवं ग्रामीण जन-उभार:** देश के विभिन्न नगरों और गाँवों में स्वतःस्फूर्त हड़तालें, विशाल जुलूस और प्रदर्शन आयोजित किए गए। जब पुलिस ने दमन का सहारा लिया, तो जनता का आक्रोश औपनिवेशिक राज्य के प्रतीकों पर टूट पड़ा। सरकारी भवनों, पुलिस थानों, डाकघरों, रेलवे स्टेशनों और टेलीग्राफ लाइनों को व्यापक रूप से निशाना बनाया गया, जो इस बात का प्रतीक था कि जनता ने औपनिवेशिक शासन के प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है।
2. **भूमिगत नेतृत्व (Underground Leadership):** यद्यपि शीर्ष नेता जेल में थे, परंतु समाजवादी और क्रांतिकारी विचारधारा के युवा नेताओं ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन को एक रणनीतिक दिशा प्रदान की। राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली और उषा मेहता जैसे दिग्गजों ने भूमिगत नेटवर्क स्थापित किए। विशेष रूप से उषा मेहता के संचालन में चलने वाले गुप्त **'कांग्रेस रेडियो' (Congress Radio)** ने देश के कोने-कोने में आंदोलनकारियों को सूचनाएँ प्रसारित कर ब्रिटिश सेंसरशिप को करारी चुनौती दी।

### 3. समानांतर सरकारों का राजनीतिक अर्थ (Political Significance of Parallel Governments)

भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे उन्नत, क्रांतिकारी और राजनीतिक रूप से सबसे महत्त्वपूर्ण आयाम देश के विभिन्न दूरस्थ अंचलों में **'समानांतर सरकारों' (Parallel Governments / Prati Sarkar)** की स्थापना था। जब औपनिवेशिक राज्य का प्रशासनिक और पुलिस तंत्र चरमरा गया, तब स्थानीय नेतृत्व और जनता ने मिलकर अपने दम पर वैकल्पिक शासन व्यवस्थाएँ खड़ी कर दीं:

- **बलिया (उत्तर प्रदेश):** चित्तू पांडे के नेतृत्व में यहाँ पहली समानांतर सरकार स्थापित हुई, जिसने जेल तोड़कर अपने नेताओं को मुक्त कराया और कुछ दिनों के लिए ही सही, संपूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।

- **तामलुक (मिदनापुर, बंगाल):** यहाँ 'जातीय सरकार' की स्थापना हुई, जिसने न केवल स्थानीय प्रशासन चलाया, बल्कि चक्रवात पीड़ितों के लिए राहत कार्य संचालित करने के लिए 'विद्युत वाहिनी' जैसे सशस्त्र स्वयंसेवक दल का गठन किया।
- **सतारा (महाराष्ट्र):** नाना पाटिल और उनके साथियों के नेतृत्व में स्थापित 'प्रति सरकार' सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली और सबसे सुव्यवस्थित समानांतर सरकार थी। इसने न्याय व्यवस्था, कर संग्रह, खाद्यान्न वितरण और ग्रामीण सुरक्षा के लिए एक स्वायत्त प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया।

राजनीति विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में इन समानांतर सरकारों की स्थापना का गहरा दार्शनिक और राजनीतिक अर्थ था। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण था कि जनता ने केवल औपनिवेशिक शासन के विरोध में हिंसक या अहिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी, बल्कि उन्होंने औपनिवेशिक राज्य की 'संप्रभुता' को पूरी तरह खारिज करते हुए अपनी **'लोकतांत्रिक एवं जन-संप्रभुता' (Popular Sovereignty)** को व्यावहारिक धरातल पर स्थापित कर दिखाया था। इन सरकारों ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता अब विदेशी शासन की मोहताज नहीं है और वह स्वशासन चलाने की पूर्ण राजनीतिक परिपक्वता रखती है।

## राजनीतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक विचारों का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन (Analytical Evaluation of Political Ideas)

### 1 औपनिवेशिक राज्य के नैतिक प्राधान्य का अंत (End of the Moral Hegemony of the Colonial State)

राजनीतिक सिद्धांत और राज्यशास्त्र (Political Science) के प्रख्यात चिंतकों–विशेषकर एंटोनियो ग्राम्शी–के अनुसार, कोई भी शासक वर्ग या औपनिवेशिक सत्ता केवल पुलिस, सेना और दंड विधान जैसे भौतिक बल (Coercion) के बल पर दीर्घकाल तक अपना आधिपत्य बनाए नहीं रख सकती। किसी भी राज्य की स्थिरता और निरंतरता के लिए एक **'नैतिक और वैचारिक प्राधान्य' (Moral and Intellectual Hegemony)** का होना अनिवार्य है, जिसके माध्यम से शासित जनता शासकों के अधिकार, उसकी वैधता और उसकी शासन प्रणाली को वैधानिक और स्वाभाविक स्वीकार करती है (जिसे 'सहमति' या Consent कहा जाता है)।

1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य के इसी नैतिक प्राधान्य को जड़ से हिलाकर रख दिया। महात्मा गांधी के "करो या मरो" के आह्वान और उसके पश्चात पूरे देश में उभरे स्वतःस्फूर्त जन-उभार ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति जो थोड़ी-बहुत वैचारिक या नैतिक स्वीकार्यता बची थी, वह पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। जब आम नागरिकों ने औपनिवेशिक थानों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और प्रतीकों को निशाना बनाया, तो यह इस बात का अकाट्य प्रमाण था कि जनता ने विदेशी शासन के प्रति अपनी 'सहमति' को पूरी तरह वापस ले लिया था। परिणामस्वरूप, ब्रिटिश राज्य अपनी नैतिक वैधता खो बैठा और उसका शासन केवल 'नग्न बल' (Naked Force) और दमन के सहारे सिमट कर रह गया। राजनीति विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, किसी भी

औपनिवेशिक राज्य के पतन की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ होती है, क्योंकि वैचारिक सहमति के समाप्त हो जाने पर शासन का पतन केवल समय का प्रश्न बन जाता है।

**2. नया राजनीतिक नेतृत्व एवं समाजवाद का प्रभाव (Emergence of New Political Leadership and the Impact of Socialism)**

भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक धारा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ उपस्थित किया। इस आंदोलन ने परामपरागत उदारवादी और गांधीवादी नेतृत्व के समानांतर एक ऐसी युवा और क्रांतिकारी नेतृत्व पंक्ति को आगे किया, जिसने स्वतंत्र भारत की राजनीतिक और आर्थिक दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई।

- **कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (CSP) का उभार:** इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि शीर्ष कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद, भूमिगत गतिविधियों का संचालन मुख्य रूप से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया। जयप्रकाश नारायण (JP), राममनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली और अशोक मेहता जैसे युवा समाजवादी विचारकों ने इस आंदोलन को केवल ब्रिटिश-विरोधी संघर्ष तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के एजेंडे से जोड़ा।
- **वैचारिक परिपक्वता:** इन नेताओं के विचारों में राष्ट्रवाद और समाजवाद का अनूठा समन्वय देखने को मिला। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ केवल गोरे शासकों के स्थान पर भूरे शासकों का आना नहीं है, बल्कि देश से आर्थिक शोषण, वर्ग-भेद और असमानता को समाप्त करना है।
- **स्वाधीनता पश्चात की राजनीति पर प्रभाव:** भारत छोड़ो आंदोलन की भट्टी में तपक कर निकले इन समाजवादी नेताओं ने स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राजनीति में विपक्षी राजनीति, श्रमिक आंदोलनों, नागरिक अधिकारों और समाजवादी नीतियों की नींव रखी। इस प्रकार, इस आंदोलन ने न केवल अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया, बल्कि भविष्य के स्वतंत्र भारतीय गणराज्य के वैचारिक और संस्थागत स्वरूप को भी गहराई से आकार दिया।

## निष्कर्ष (Findings)

प्रस्तुत शोध पत्र के अंतर्गत निर्धारित शोध उद्देश्यों, शोध प्रश्नों एवं परिकल्पना (Hypothesis) के गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन के पश्चात् निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष प्राप्त होते हैं:

**1. ऐतिहासिक एवं राजनीतिक उत्प्रेरक कारकों का समाधान -** शोध से यह सिद्ध होता है कि 1942 के 'भारत छोड़ो' आह्वान के पीछे मार्च 1942 में **क्रिप्स मिशन की पूर्ण विफलता** मुख्य राजनीतिक उत्प्रेरक थी, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश हुकूमत भारत को वास्तविक स्वायत्तता देने के पक्ष में नहीं थी। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी बेहिसाब **मुद्रास्फीति, खाद्यान्न संकट एवं आवश्यक वस्तुओं की किल्लत** तथा दक्षिण-पूर्व एशिया (बर्मा एवं सिंगापुर) से ब्रिटिश सेनाओं के पीछे हटने व

भारतीय नागरिकों के साथ किए गए नस्लीय भेदभाव ने जन-आसंतोष को चरम पर पहुँचा दिया, जिसने गांधी जी एवं कांग्रेस को तत्काल एवं पूर्ण स्वतंत्रता के लिए आक्रामक आह्वान करने पर विवश किया।

**2. स्वतःस्फूर्तता, विकेंद्रीकरण एवं जन-सहभागिता -** 9 अगस्त 1942 की भोर में 'ऑपरेशन ज़ीरो अवर' के तहत शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारी के पश्चात् आंदोलन समाप्त होने के स्थान पर **स्वतःस्फूर्त (Spontaneous) एवं विकेंद्रीकृत** हो गया। शीर्ष नेतृत्व की अनुपस्थिति में युवाओं, छात्रों, महिलाओं और किसानों ने स्वयं आंदोलन की कमान संभाली। शहरों में हड़तालों और सरकारी प्रतीकों पर हमलों के साथ-साथ जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, और उषा मेहता (गुप्त 'कांग्रेस रेडियो') जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को तकनीकी एवं वैचारिक दिशा प्रदान की, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय चेतना जन-सामान्य का संप्रभु संकल्प बन चुकी थी।

**3. समानांतर सरकारों की चुनौती एवं जन-संप्रभुता -** बलिया (उत्तर प्रदेश), तामलुक (बंगाल) और सतारा (महाराष्ट्र) में स्थापित समानांतर सरकारों ('प्रति सरकार' या 'जातीय सरकार') ने औपनिवेशिक राज्य की प्रशासनिक एवं नैतिक वैधता को सीधे चुनौती दी। इन समानांतर सरकारों ने यह ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत किया कि जनता ने न केवल ब्रिटिश सत्ता को खारिज किया, बल्कि औपनिवेशिक राज्य के विकल्प के रूप में अपनी **लोकतांत्रिक एवं जन-संप्रभुता (Popular Sovereignty)** को व्यावहारिक धरातल पर सफलतापूर्वक संचालित करके दिखाया।

**4. प्रशासनिक व सैन्य ढाँचे का बिखराव एवं वैधता का अंत -** शोध की **परिकल्पना पूर्णतः सत्य एवं सत्यापित प्रमाणित होती है**। यद्यपि औपनिवेशिक राज्य ने अत्यधिक सैन्य बल प्रयोग, सामूहिक जुर्माने और 1,00,000 से अधिक गिरफ्तारियों के माध्यम से आंदोलन को अल्पकाल के लिए दबा दिया, परंतु इसने ब्रिटिश शासन के प्रशासनिक व पुलिस ढाँचे में कार्यरत भारतीय कर्मचारियों की वफादारी को पूरी तरह हिला दिया। ब्रिटिश शासन का 'नैतिक प्राधान्य' (Moral Hegemony) समाप्त हो गया और उसका शासन केवल 'नग्न बल' पर सिमट गया, जिससे यह सिद्ध हो गया कि केवल सैन्य शक्ति के बल पर भारत पर दीर्घकालिक शासन करना असंभव था।

**5. अंतर्राष्ट्रीय दबाव एवं सत्ता हस्तांतरण की अनिवार्यता -** इस अभूतपूर्व जन-उभार ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मित्र राष्ट्रों (विशेष रूप से अमरीका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट) को ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर भारत को स्वतंत्रता देने हेतु दबाव बनाने पर मजबूर किया। परिणामतः, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते ही वेवैल योजना, कैबिनेट मिशन (1946) और अंततः 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इसी 1942 के आंदोलन की प्रत्यक्ष परिणति थे, जिसने 1947 में सत्ता हस्तांतरण को एक अनिवार्य एवं अपरिहार्य ऐतिहासिक घटना बना दिया।

## सुझाव (Recommendations)

- स्वतंत्रता आंदोलन के अध्ययनों में केवल शीर्ष नेतृत्व के स्थान पर स्थानीय समानांतर सरकारों एवं जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के योगदान पर और अधिक गहन शोध किया जाना चाहिए।

- औपनिवेशिक राज्य द्वारा किए गए दमन और उसके भारतीय समाज पर पड़े सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में और अधिक समावेशित किया जाना चाहिए।

## संदर्भ ग्रंथ सूची (References)


1. आजाद, मऊ. ए. (1988). *इण्डिया विन्स फ्रीडम* (अंतिम एवं संपूर्ण संस्करण). ओरिएंट लॉन्गमैन.
2. गुहा, र. (2007). *इण्डिया आफ्टर गांधी: द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी*. हार्परकॉलिन्स.
3. चोपड़ा, पी. एन. (संपादक). (1971). *क्विट इण्डिया मूवमेंट: ब्रिटिश सीक्रेट रिपोर्ट्स*. फरीदाबाद: हरियाणा ऐतिहासिक अध्ययन संस्थान.
4. गुप्ता, पी. एस. (संपादक). (1997). *टुवर्ड्स फ्रीडम: डॉक्यूमेंट्स ऑन द मूवमेंट फॉर इण्डिपेंडेंस इन इण्डिया, 1943-1944* (भाग 1 एवं 2). इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एवं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
5. चंद्र, बि. (1989). *इण्डियाज स्ट्रगल फॉर इण्डिपेंडेंस (1857-1947)*. पेंगुइन बुक्स इंडिया.
6. चंद्र, बि., मृदुला, म., आदित्य, म., सुचेता, म., एवं के. एन., पा. (2009). *भारत का स्वतंत्रता संघर्ष*. हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय.
7. ताराचंद. (1972). *हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इण्डिया* (खंड 4). सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार.
8. पाटिल, वा. टी. (1984). *गांधी, नेहरू एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट*. बी. आर. पब्लिशिंग कॉरपोरेशन.
9. पांडेय, गी. (1988). *द इंडियन नेशन इन 1942*. सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेज एवं के. पी. बागची एंड कंपनी.
10. बासु, सं. (2003). *जस्टिस इन द फॉरेस्ट: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द तामलुक जातीय सरकार*. ओरिएंट ब्लैकस्वांस.
11. भाटिया, ल. म. (1982). *द लास्ट फेज़ ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया*. विकास पब्लिशिंग हाउस.
12. भल्ला, सं. (संपादक). (2002). *द क्विट इंडिया मूवमेंट: द फाइनल फेज़*. नेशनल बुक ट्रस्ट.
13. मोंटगोमरी, जॉ. (1970). *द स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशन ऑफ 1942*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
14. लोहिया, रा. (1955). *गुप्त क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम*. नवहिंद प्रकाशन.
15. सरकार, सु. (1983). *मॉडर्न इंडिया: 1885-1947*. मैकमिलन इंडिया लिमिटेड.
16. हचिंस, फ्र. जी. (1971). *स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशन: द क्विट इंडिया मूवमेंट*. मनोहर बुक सर्विस.

## ISARA INSTITUTE OF MANAGEMENT & PROFESSIONAL STUDIES

WWW.IIMPS.IN

EARN YOUR

# MBA



Accreditation & Ranking

UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

011-41005174

RESEARCH GATEWAY

STOP PLAGIARISM

1 Submit your content in Word File.

2 Get report in 48 hrs.

3 *Missing content or references will be fixed.

4 Citation for your work.

5 Get accurate user friendly report.

researchgateway.in | info@researchgateway.in

+91-9205579779

AROGYAM ONLINE

Arogyam Ayurveda

Holistic Healing through herbs

100% NATURAL

## PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD

BLUE — Calms your Child's Mind & Body

YELLOW — Promotes Concentration, Stimulates the Memory

PINK — Evokes Empathy, makes your Child Calm

RED — Excites and energizes your Child's body

GREEN — Improves Reading speed and Comprehension

www.parivartan4u.com

Confuse about your children's future?

**भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध**

**ISSN 2321 – 9726**

**WWW.BHARTIYASHODH.COM**

**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY**

**ISSN – 2250 – 1959 (0) 2348 – 9367 (P)**

**WWW.IRJMST.COM**

**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF COMMERCE, ARTS AND SCIENCE**

**ISSN 2319 – 9202**

**WWW.CASIRJ.COM**

**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES**

**ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P)**

**WWW.IRJMSH.COM**

**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE ENGINEERING AND TECHNOLOGY**

**ISSN 2454-3195 (online)**

**WWW.RJSET.COM**

**INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION**

**ISSN 2582-5445**

**WWW.IRJMSI.COM**

**JOURNAL OF LEGAL STUDIES,POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH**

**WWW.JLPER.COM**